>

Title : The Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment laid a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : मैं यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन भाग- II. दिनांक 1 सितम्बर 2004 में प्रकाशित लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-क के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की छत्तीसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/िटप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की चौथी रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2013-14 की अनुदान मांगों के संबंध में है। यह रिपोर्ट लोक सभा में 2 मई, 2013 को तथा राज्य सभा में उसी दिन प्रस्तुत की गई थी। छत्तीसवीं रिपोर्ट में 12 सिफारिशें दी गई थीं जिनके संबंध में मंत्रालय के सामान्य कार्य निष्पादन, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के विकास तथा नशीली दवा दुरूपयोग एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजनाओं से है। छत्तीसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/िटप्पणियों के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ समिति को 2 अगस्त, 2013 को भेजी गइ थीं।

समिति द्वारा अपनी छत्तीसवीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों/िटप्पणियों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति सभापटल पर प्रस्तुत मेरे वक्तव्य के साथ दिए गए अनुबंध में दी गई है। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा गया समझा जाए।